शिक्षक - रवि शंकर राय
दिनांक - 08-08-2020

विषय - अर्थशास्त्र
वर्ग - B.A-II

भारतीय उद्योगों के विकास तथा आधुनिकीकरण को बाधित किया।

VI) विदेशी निवेश के लिए एक सीमित बहुराष्ट्रीय कंपनियों (Multi-National companies) को दी गई जो इस देश में अपने सहायक अथवा उपांग उद्योग लगा सकती थी।

1977 की औद्योगिक नीति
(Industrial policy statement, 1977)

वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति एक भिन्न राजनीतिक समूह की देन हैं तथा उस समय राजनीतिक सरगर्मी भी भिन्न थी। तत्कालीन शासन में स्वदेशी विरोधी आवाज का प्रभुत्व था एवं इन नेताओं का झुकाव अर्थव्यवस्था के गांधीवादी-समाजवादी विचारधारा के प्रति था। इस विचारधारा के तत्व 1977 की औद्योगिक नीति में देखे जा सकते हैं:-

i) अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया (यह वर्ष 1973 की औद्योगिक नीति के विपरीत था, जिसने विदेशी निवेश को तकनीकी हस्तांतरण द्वारा उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जहाँ पूँजी तथा आवश्यक तकनीक की कमी थी)। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो विदेशी निवेश को पूर्ण रूप से नकार दिया गया।

ii) ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया गया तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों को नए ढंग से परिभाषित किया गया।

iii) विकेंद्रित औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया ताकि आम लोगों को औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जोड़ने का उद्देश्य पूरा हो सके। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विस्तार वृहत पैमाने

पर करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों (District Industries Centres - DICs) की स्थापना की गयी।

iv) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया तथा खादी व ग्रामीण उद्योगों की पुनर्संरचना की गई।

v) दिन-प्रतिदिन के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उत्पादन स्तर पर गंभीर रूप से ध्यान दिया गया।

1980 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव

(Industrial policy Resolution, 1980)

1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः केन्द्र में वापस आई। नई सरकार ने 1980 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में 1977 के औद्योगिक नीति को कुछ अपवादों के साथ संशोधित किया। इस नीति द्वारा दिए कुछ मुख्य प्रस्ताव थे—

i) तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गयी (यह 1973 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों जैसा ही था।)।

ii) 'MRTP सीमा' में संशोधन कर इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके।

iii) जिला उद्योग केन्द्रों (DICs) को जारी रखा गया।

iv) औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बना दिया गया।

v) आमतौर पर निजी उद्योगों के विस्तार के उदारवादी रुख अपनाया गया।

1985 तथा 1986 की औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव
(Industrial policy Resolution, 1985, 1986)

1985 तथा 1986 में सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव लगभग एकसमान था। 1986 की औद्योगिक नीति ने 1985 की औद्योगिक नीति को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इन नीतियों की मुख्य आकर्षण निम्नलिखित थे :—

i) विदेशी निवेश को अधिक सरल बनाया दिया गया तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया। विदेशी निवेश की मुख्य पद्धति पहले जैसी ही थी। अर्थात तकनीकी हस्तांतरण, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनीयाँ भारतीय अपांग उद्योग में 49% इक्विटी के स्ताम्रीदार हो सकते थे, अन्य 51% शायर इनके भारतीय स्ताम्रीदार के हाथ में होना था।

ii) 'MRTP सीमा' को संशोधित किया गया तथा इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया ताकी बड़ी कंपनीयों को प्रत्सा-हित किया जा सके।

iii) औद्योगिक लाईसेंसिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया। अनिवार्य लाइसेंसिंग अब 64 उद्योगों के लिए ही मात्र था।

iv) 'सनराइज' उद्योग, जैसे- दूरसंचार, कम्प्यूटरीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक पर अधिक बल दिया गया।

v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा लाभ पर अधिक बल दिया गया।

vi) आयात किए गए कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला।

vii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) की व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा के उपयोग के संदर्भ में कुछ रियायतें दी गयी ताकी आवश्यक तकनीक को भारतीय उद्योग में सम्मिलित किया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया जा सके।

viii) कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया तथा इस क्षेत्र के लिए नए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, सरकार द्वारा इस संदर्भ में अनेक तकनीकी मिशनों की शुरुआत की गयी।

सरकार द्वारा इन नीतियों पर विचार उस समय किया जा रहा था, जब विश्व के विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के निर्माण पर जोर दे रहे थे तथा एक नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था सच होती नजर आ रही थी। ज्यों ही विश्व एक वृहद बजार बनेगा इसकी आपूर्ति मात्र बड़ी कंपनियों द्वारा ही की जा सकेगी। इन औद्योगिक प्रावधानों का प्रयास अर्थव्यवस्था का उदारीकरण था। यह कार्य बैगैर किसी "आर्थिक सुधार" के नारे के किया जाना था। तत्कालीन सरकार की यह इच्छा थी कि उस प्रकार के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जाए जैसे कि 1991 के पश्चात हुई, लेकिन इसके लिए आवश्यक राजनीतिक समर्थन की कमी थी।